श्री गंगाई विनयागर टैंपल और एक अन्य

बनाम

मीनाक्षी अम्मल और अन्य

(सिविल अपील सं. 4227 / 2003)

09 अक्टूबर, 2014

[अनिल आर. डेव, विक्रमजीत सेन और पिनाकी चंद्र गौस, न्यायाधिपतिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 2, नियम 2 और धारा 11 - पूर्व न्याय ज्यूडिकेटा - की प्रयोज्यात - अपीलकर्ता-ट्रस्ट की इसके ट्रस्टियों के माध्यम से कि नष्ट संपत्ति के उत्तरदाताओं/किरायेदारों को पूर्व न्याय के सिद्धांत द्वारा ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देने से रोक दिया गया था, विशेष रूप से नष्ट संपत्ति ट्रस्ट के स्वामित्व को। क्योंकि किरायेदारों ने केवल एक अपील दायर की, यानी एक मुकदमे (ओ.एस.6/78) से उत्पन्न, दो अन्य मुकदमों (ओ.एस. 5/78 और 7/78) में विचारण कोर्ट द्वारा पहुंचे समान निष्कर्षों पर हमला किए बिना - तीनों मुकदमे जुड़े हुए थे, एक साथ सुने गए, और एक सामान्य निर्णय के माध्यम से ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए, लेकिन तीन अलग-अलग डिक्री द्वारा -अभिनिर्धारित किया गया: अपीलकर्ताओं की याचिका मान्य थी - किरायेदार की ओर से दलीलें तीनों मुकदमों में आम थीं - डिक्री, से जुड़े हुए मुकदमे से उत्पन्न हुई और सामान्य निर्णय, यदि चुनौती नहीं दी गई, तो "पूर्व मुकदमे" के चरित्र में रूपांतरित हो जाता है - ओएस 5/78 और ओ.एस.7/78 में डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने में विफल या उपेक्षित या ठोस रूप से टाला जाना। वादी किरायेदारों के मामले को स्थायी रूप से सील और बंद कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ पूर्व निर्णय लागू हुआ था।

पूर्व न्याय - निर्णय की न्यायिक स्थिति और उसकी प्रयोज्यता पर चर्चा की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने, अभिनिर्धारित किया: तीनों वर्षों में किरायेदार की दलीलों का समग्र और व्यापक अध्ययन करने पर, यह अपरिहार्य है कि किरायेदार ने जानबूझकर, सीधे और स्पष्ट रूप से अपनी दलीलों में ध्वस्त परिसर के स्वामित्व और ट्रस्टियों की जमीन को स्थानांतरित करने वालों को हस्तांतरित करने की कानूनी क्षमता का सवाल उठाया था। यह सामान्य सूत्र है जो तीनों साल में किरायेदार की दलीलों से गुजरता है। यह सच है कि यदि ओ एस संख्या 5/78 सरलता से निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा था, और ट्रस्टियों और ट्रांसफरियों के रुख के मद्देनजर कि किरायेदारों को उनके निष्कासन के संबंध में कोई खतरा नहीं बढ़ाया गया था, तो स्वामित्व के लिए कोई भी संदर्भ या चुनौती पूरी तरह से अप्रासंगिक थी। लेकिन स्वामित्व का मुद्दा विशेष रूप से किरायेदार द्वारा उठाया गया था, जिसके कारण यह तीनों मुकदमों में सीधे और बड़े पैमाने पर मुद्दा बन गया था। जहां तक वाद संख्या 6/78 और 7/78 का सवाल है, वे भी किराए की वसूली के लिए सरल मुकदमे थे जिनमें स्वामित्व से संबंधित बचाव भी प्रासंगिक नहीं था; किरायेदार के पास ओएस 6/78 में अपील दायर करने का कोई ठोस कारण नहीं उत्पन्न हुआ था, क्योंकि डिक्री का मौद्रिक हिस्सा अपेक्षाकृत महत्वहीन था। जाहिर है, किरायेदार का संकल्प मुकदमे में स्वामित्व को केंद्रीय विवाद बनाना था और इन परिस्थितियों में स्वामित्व के पहलू पर गोलमोल बातें करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तार्किक रूप से, यदि स्वामित्व का प्रश्न प्रासंगिक था और ओ.एस.6/78 में विचार करने योग्य था, यह ओएस संख्या 5/78 में भी प्रासंगिक था। इस तरह से देखने पर, यह एक अपरिहार्य निष्कर्ष है कि किरायेदार द्वारा ओ.एस. 5/78 के संबंध में भी अपील दायर की जानी चाहिए थी, पूर्व न्याय की कठोरता को आमंत्रित करने के डर से और "खारिज" आदेश को सही करने के लिए भी। एक बार जब यह माना गया कि उसके पक्ष में कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ था, तो किरायेदार पूरी तरह से गैर-मुकदमा हो गया था

और मुकदमा 'खारिज' कर दिया गया था। उस खोज को नज़रअंदाज करना और उसे अंतिम मान लेना उस निष्कर्ष को बदलने के लिए अभेद्य बना देता है। ओएस 5/78 और ओएस 7/78 में डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने में असफल या उपेक्षित या ठोस रूप से टालने के कारण प्रतिवादी का मामला स्थायी रूप से सील कर दिया गया था और फौजदारी कर दी गई थी क्योंकि उनके खिलाफ पूर्व न्याय लागू हुआ था। (पैरा 23, 24) (872-एफ-एच; 873-ए-डी; 874-डी, ई)

प्रीमियर टायर्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम 1993 (पूरक) 2 एससीसी 146; लोनंकुट्टी बनाम थॉम्मन (1976) 3 एससीसी 528: 1976 (0) सप्ल.-एससीआर 74; नारायण प्रभु वेंकटेश्वर प्रभु बनाम नारायण प्रभु कृष्ण प्रभु (1977) 2 एससीसी 181: 1977 (2) एससीआर 636; श्योदान सिंह बनाम दरियाओ कुँवर (1966) 3 एससीआर 300; चितिवलसा जूट मिल्स बनाम जेपी रीवा सीमेंट (2004) 3 एससीसी 85; सज्जादानशीन सईद बनाम मूसा दादाभाई उमर एआईआर 2000 एससी 1238: 2000 (1) एससीआर 1095; ईशर सिंह बनाम सरवन सिंह एआईआर 1965 एससी 948; और प्रागदासजी गुरु भगवानदासजी बनाम पटेल ईश्वरलालभाई नरसीभाई एआईआर 1952 एससी 143: 1952 एससीआर 513 का उल्लेख किया गया है।

लछमी बनाम भुल्ली एआईआर (1927) लाह 289; पंचंदा वेलन बनाम वैथिनाथ सस्त्रियल आईएलआर (1906) 29 मैड 333; बी. शंकर सहाय बनाम बी. भागवत सहाय एआईआर 1946 अवध 33 (एफबी); ज़हरिया बनाम देबिया आईएलआर (1911) 33 सभी 51; आईएसयूपी ऑल बनाम गौर चंद्र देब 37 कैल एलजे 184: एआईआर 1923 कैल 496; मिसेज गेट्रूड ओस्टेस बनाम मिसेज मिलिसेंट डी'सिल्वा आईएलआर 12 पैट 139: एआईआर 1933 पैट 78; असरार अहमद बनाम दरगाह कमेटी, अजमेर एआईआर 1947 पीसी 1 और श्योपरसेन सिंह बनाम रामनंदन प्रसाद सिंह (1915-16) 43 आई.ए.91 - संदर्भित किया गया।

होग बनाम न्यू जर्सी (1958) 356 यू.एस. 464 - संदर्भित किया गया।

केस कानून संदर्भ

1993 (पूरक) 2 एससीसी 146 संदर्भित किया गया पैरा 5

1976 (0) पूरक एससीआर 74 संदर्भित किया गया पैरा 6

1977 (2) एससीआर 636 संदर्भित किया गया पैरा 6

(1966) 3 एससीआर 300 संदर्भित किया गया पैरा 19

एआईआर (1927) लाह 289 संदर्भित किया गया पैरा 20

आई. एल. आर. (1906) 29 मैड 333 संदर्भित किया गया पैरा 20

एआईआर 1946 अवध 33 (एफ. बी.) संदर्भित किया गया पैरा 20

आई. एल. आर. (1911) 33 सभी 51 संदर्भित किया गया पैरा 21

ए. आई. आर. 1923 कैल 496 संदर्भित किया गया पैरा 21

ए. आई. आर 1933 पैट 78 संदर्भित किया गया पैरा 21

(2004) 3 एससीसी 85 संदर्भित किया गया पैरा 22

2000 (1) एससीआर 1095 संदर्भित किया गया पैरा 23

(1958) 356 अमेरिका 464 संदर्भित किया गया पैरा 23

ए. आई. आर 1965 एस. सी. 948 संदर्भित किया गया पैरा 23

एआईआर 1947 पी. सी. 1 संदर्भित किया गया पैरा 23

1952 एससीआर 513 संदर्भित किया गया पैरा 23

(1915-16) 43 I.A.91 संदर्भित किया गया है पैरा 23

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 4227/2003

एल. पी. ए. सं. 17 /1998 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06-01-2003 से।

जयदीप गुप्ता, संजय आर. हेगड़े, एस. नितिन, कुणाल चटर्जी, अपीलार्थियों के लिए।

के. राम मूर्ति, सुरेंद्र नाथ, गोविंद मनोहरन, सेंथिल जगदीशन, श्रुति लायर, वी. रामसुब्रमण्यन, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय विक्रमजीत सेन, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था। 1: इस अपील के निर्धारण के दोरान तथ्यो और घटनाओ की भूलभूलैया और कानूनी उलझनो की भूलभूलैया हमारे सामने आती है। मूलत: यह न्यायिक निर्णय के सिद्धांत का दायरा और व्यापकता है जो कि विवाद के केंद्र में है। इसके अतिरिक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II नियम 2 (संक्षिप्तता के लिए "सीपीसी"), जो कि न्याय के एक अन्य पहलू को भी स्थापित करता है, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अपने न्यासियो (इसके बाद 'ट्रस्ट' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से अपीलकर्ता का तर्क यह है कि हस्तांतरित संपत्ति के उत्तरदाताओं/किरायेदारों (संक्षिप्तता के लिए किरायेदारों) को पूर्व न्याय सिद्धांत द्वारा विचारण कोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देने से रोक दिया गया है। विशेष रूप से नष्ट हो चुकी संपत्ति पर ट्रस्ट का स्वामित्व, क्योंकि उक्त किरायेदारों ने केवल एक अपील दायर की है, यानी ओएस 6/78 से उत्पन्न, ओएस 5/78 और ओएस 7/78 में विचारण कोर्ट द्वारा पहुंचे समान निष्कर्षों को चुनौती दिये बिना।

2. निर्विवाद तथ्य यह है कि पहले प्रतिवादी/किरायेदारों के पति (कन्नल्या चेट्टियार और एक अन्य व्यक्ति वेंकटराम केडियार) ने सेथुरामा चेट्टियार से 1.3.1953 को मासिक किराए रूपये 150/- पर 12 साल की अवधि के लिए भूमि पट्टे पर ली थी।

किरायेदारों को वाद की जमीन पर अपनी लागत पर एक सिनेमा थिएटर बनाने की अनुमति दी गई थी, जिसे उन्होंने 'राजा टॉकीज' के नाम और शैली में बनाया था, जो अभी भी अस्तित्व में है। 1959 में एक साझेदार की मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी नंबर 1 के पति को 'राजा टॉकीज़' का एकमात्र स्वामित्व प्राप्त हुआ। 8.11.1967 को प्रतिवादी नंबर 1 के पति और अपीलकर्ता ट्रस्ट, गंगई विनयगर मंदिर के बीच इसके ट्रस्टी के अध्यक्ष श्री सेथुरामा चेट्टियार के माध्यम से 1.1.1968 से शुरू होने वाली 15 साल की अवधि के लिए एक नया पंजीकृत नोटेयर लीज डीड निष्पादित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 के पति की मृत्यु के परिणामस्वरूप, वह अपने बच्चों के साथ अपने दिवंगत पति के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में किरायेदार के रूप में बनी रही। यह भी विवाद में नहीं है कि ट्रस्ट ने मुकदमे की संपत्ति सर्वश्री पी.लक्ष्मणन, पी.वाडिवेलु और पी.साईभाभा को बेच दी, जिन्हें किरायेदारों ने ओएस 5/ 78 में प्रतिवादी 7 से 9 के रूप में शामिल किया था। किरायेदारों को इस लेन-देन के बारे में 14.10.1976 को सूचित किया गया, और उनसे नए मालिकों के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का आह्वान किया गया। नतीजा यह हुआ कि 1976 में ही, किरायेदारों ने ओएस 5/78 (पुनः क्रमांकित) दायर किया, जिसमें उन्होंने मुकदमे की जमीन की बिक्री को इस शर्त पर चुनौती दी थी कि कि ट्रस्ट की संपत्ति के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया था क्योंकि यह एक सार्वजनिक ट्रस्ट था, और इसके अलावा, उपरोक्त लेनदेन के बाद, किरायेदारों (ओ.एस.5/78 में वादी) ने प्रतिवादियों 7 से 9 (इसके बाद 'अंतरिती' कहा जाएगा)। सहित प्रतिवादियों के हाथों अपनी बेदखली की आशंका जताई थी। प्रार्थनाओं को बुनियादी तौर पर पुन: प्रस्तुत किया गया है। इस मुकदमे में, ट्रस्ट के साथ-साथ स्थानांतरित लोगों ने अपने-अपने लिखित बयानों में अनुरोध किया कि उन्होंने

किरायेदारों को कानूनी प्रक्रिया के बिना बेदखल करने की न तो धमकी दी थी और न ही उन्हें बेदखल करने का कोई इरादा रखा था।

3. मुकदमेबाजी की इस पहली लड़ाई की अगली कड़ी ट्रस्ट द्वारा दो मुकदमे दायर करना था, जो कि ओ एस 6/78 और ओ एस 7/78 थे, जिसमें किरायेदारों से बकाया किराए का दावा किया गया था। (हमारे सामने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक जिसमें अंतरितियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था) उनके द्वारा अंतरितियों को मुकदमे की भूमि के हस्तांतरण से पहले की अवधि से संबंधित। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दलीलों के बावजूद, ओ एस 5/78 को 'खारिज' कर दिया गया। ओएस 6/78 को आंशिक रूप से डिक्री किया गया था; जबकि ओ एस 7/78 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इस मुकदमे में किराए के बकाया का कथित दावा मान्य नहीं था क्योंकि उक्त भूमि मुकदमे की भूमि का हिस्सा थी और उसमें शामिल थी जो ओएस 6/78 का विषय था और, तदनुसार, दावा कवर किया गया था और उसमें शामिल किया गया था। किरायेदारों ने ओएस 5/78 और ओ एस 7/78 के संबंध में कोई अपील दायर नहीं की है; और ट्रस्ट ने उनके मुक़दमे ओ एस 7/78 को ख़ारिज करने पर कोई अपील दायर नहीं की है। पांडिचेरी में द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत द्वारा 6.11.1982 को पारित एक सामान्य निर्णय द्वारा, सामान्य साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के बाद, सभी तीन मुकदमों का फैसला किया गया है। इस निर्णय के अनुसरण में तीन अलग-अलग आदेश निकाले गए हैं।

4. ओ एस 5/78 में निहित प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं:

(I) वादी के पट्टाधिकार को स्थापित करना और पट्टा अवधि के अंत तक अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति पर कब्ज़ा रखना। 1-1-1983; और

ii) 1-1-1983 तक प्रतिवादियों, उनके एजेंटों, नौकरों और अन्य प्रतिनिधियों को वादी के शांतिपूर्ण कब्जे और मुकदमे की संपत्ति के आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए।

(iii) प्रतिवादियों को वादी को मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश देना; और

(iv) ऐसी अन्य राहत प्रदान करें जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में आदेश देने में प्रसन्न हो।

यह उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 पर आधारित किसी मुद्दे को तैयार करने के लिए दबाव नहीं डाला था। ओएस .5/78 में वादपत्र में, किरायेदार ने अनुरोध किया था कि प्रतिवादियों को "संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह प्रथम प्रतिवादी की ट्रस्ट संपत्ति है और इस तरह विश्वास का उल्लंघन होने के कारण अलगाव पूरी तरह से शून्य होगा। .... प्रतिवादी 7 से 9 के पक्ष में अलगाव शून्य होने के कारण, उनके पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है... कार्रवाई का कारण 30.6.1976 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी 2 से 6 ने मुकदमे की संपत्ति को प्रतिवादी 7 से 9 को हस्तांतरित करने का इरादा किया और, उसके बाद, जब प्रतिवादी वादी के कब्जे को परेशान करने की धमकी दे रहे हैं।" इन दलीलों की विशिष्टता के बावजूद किरायेदारों ने अंतरिती के शीर्षक के संबंध में किसी भी राहत के लिए प्रार्थना नहीं की थी। फिर भी, ध्यान से विचार करने पर हमें यह प्रतीत होता है कि, अजीब शब्दों में भले ही यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो, पहली प्रार्थना इसी प्रार्थना को स्पष्ट करने का प्रयास करती है। किसी भी घटना में, दलीलें इस धारणा की नींव रखने के लिए पर्याप्त हैं कि किरायेदार भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण पर हमला करने के इच्छुक थे। ऐसी स्थिति में, आदेश II नियम 2 सीपीसी का प्रतिबंध किरायेदारों के

खिलाफ प्रभावी हो जाएगा। वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक मुद्दा (जिसके सबूत का भार किरायेदारों पर निर्धारित किया गया था) इस प्रकार है: -

(2) क्या वाद संपत्ति सेथुरामा चेट्टियर की निजी संपत्ति नहीं है और क्या वादी को मकान मालिक या उसके विक्रेताओं के स्वामित्व पर सवाल उठाने से रोका नहीं गया है। कानूनी उलझनों की एक भूलभुलैया हमें इस दौरान सामना करती है।

हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी करते हैं कि क्या किरायेदारों (ओ.एस. 5/78 में) ने मुकदमे के कानूनी चरित्र को छुए बिना, केवल सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के हाथों बेदखली का डर या आशंका व्यक्त की थी, संपत्ति के साथ-साथ ट्रस्ट की कानूनी स्वामित्व और क्षमता (प्रतिवादी 2 से 6) इसे हस्तांतरितियों (प्रतिवादी 7 से 9) को हस्तांतरित करने के लिए; आदेश II नियम 2 आकर्षित नहीं होता। ये प्रश्न बाद में उस स्थिति में उठाए जा सकते थे जब नए मालिकों, अर्थात् प्रतिवादी 7 से 9 को किरायेदारों के खिलाफ अदालत के समक्ष कोई कार्रवाई या दावा लाना था। यही कारण है कि हम आक्षेपित आदेश में खंडपीठ के निर्धारण से सहमत होने में असमर्थ हैं कि यह मुद्दा वाद ओएस 5/78 के लिए केंद्रीय नहीं था और इसलिए, किरायेदारों की विफलता के बावजूद पूर्व न्याय ओएस 5/78 में फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए लागू नहीं हुआ। प्रतिवादियों के लिखित बयान के मद्देनजर हम सूट ओएस 5/78 के 'खारिज' के आदेश को कायम नहीं रख सकते, यहां तक कि उस मामले में मुकदमा चलाने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए, हमें ऐसा लगता है कि वहां से अपील करना आवश्यक था। हम यह भी मानते हैं कि यह बेहद प्रासंगिक है कि किरायेदारों ने ओएस 7/78 में फैसले और डिक्री पर हमला नहीं किया क्योंकि इसमें यह दोहराया गया था कि ट्रस्ट सेथुराम चेट्टियार की निजी संपत्ति थी। इसलिए यह खोज अंतिम रूप ले चुकी है। ओएस .5/78 और ओएस 7/78 दोनों में, जिसके बाद चरित्र को "पूर्व सूट" मान लिया गया। चूंकि ट्रस्ट ने ओएस 7/78 के

खिलाफ अपील भी दायर नहीं की थी, इसलिए इसके खिलाफ न्यायिक निर्णय दो पहलुओं पर लागू हुआ, पहला यह कि दो किरायेदारियां थीं। - और दूसरी बात यह कि किराए का कोई भी बकाया ओएस 6/78 में दावा किए गए दावे के अलावा अलग से अर्जित किया गया था।

5. ऐसी ही परिस्थितियों में एक समन्वय पीठ ने प्रीमियर टायर्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, 1993 (सप्ल.) 2 एससीसी 146 में निष्कर्ष निकाला था कि किसी डिक्री के खिलाफ अपील दाखिल न करने का प्रभाव यह होता है कि वह अंतिम रूप ले लेती है और यह परिणाम तार्किक रूप से तब होता है जब किसी संबंधित मुकदमे में डिक्री के खिलाफ अपील नहीं की जाती है। यह, जैसा कि मौजूदा मामले में है, सभी मुकदमों (ओ.एस.5/78 और ओएस.7/78) की नसों में व्याप्त है क्योंकि सामान्य मुद्दे तय किए गए थे, एक सामान्य परीक्षण आयोजित किया गया था, सामान्य साक्ष्य दर्ज किए गए थे, और एक सामान्य निर्णय प्रतिपादित किया गया था. हमें ऐसा लगता है कि खंडपीठ ने प्रीमियर टायर्स में निर्णय को अलग करने और फिर उससे विचलित होने के लिए ओएस 5/78 में अप्रासंगिक होने वाले शीर्षक को चुनौती की द्वंद्वात्मकता को अपनाया था। प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्येक मुकदमे में सभी कारक समान हैं, अर्थात्, मुद्दों, परीक्षण और फैसले की समानता, उन्हें अलग करने के किसी भी प्रयास को निरर्थकता में डालती है। ओएस 5/78 (उपरोक्त) में वाद संख्या 2 को पढ़ने से यह विचार करना असंभव हो जाएगा कि उस मामले में विवाद की रूपरेखा केवल ट्रस्ट द्वारा किरायेदारों को स्थानांतरितियों के रूप में जबरन बेदखल करने की आशंका से संबंधित है। अन्यथा, तनकी संख्या 2 ओएस 5/78 के निर्णय के लिए स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक था और एक नगण्य अधिशेष था। इसके अलावा, मुकदमे को खारिज करना, भले ही यह विशिष्ट और अस्थिर आधार पर था कि ओ एस 5/78 दाखिल करने को उचित ठहराने के लिए कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ था, इससे

यह निष्कर्ष निकलेगा कि किरायेदार, उसके बाद, वाद संपत्ति में किसी अधिकार से वंचित थे। यदि पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो ओएस 5/78 की खारिज, यकीनन, किरायेदार के हित के लिए घातक हो जाएगी।

6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, आक्षेपित निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि उसके सामने एकमात्र प्रश्न यह था कि पूर्व न्याय के सिद्धांत किरायेदार के खिलाफ लागू होते हैं क्योंकि उसने लापरवाही से यदि ठोस ढंग से नहीं तो अपील ओएस .5/ 78 में फैसले की अपील नही की। अपने तर्क की सीमा पर, इसने प्रीमियर टायर्स में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रस्ट की ओर से उठाया गया तर्क "त्रुटिहीन होगा और इसे केवल स्वीकार करना होगा यदि अपीलकर्ता यह स्थापित करने में सफल हो जाता है कि ओएस 5/78 में मुद्दा संख्या 2, वास्तव में, एक मुद्दा जो सीधे तौर पर और पर्याप्त रूप से उस मुकदमे में विचार के लिए उठा था और उस पर अपीलकर्ता के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज किए गए थे। पक्षों के लिए विद्वान वकील से यह अपेक्षा की गई होगी कि उन्होंने इस न्यायालय की विभिन्न समन्वय पीठों के दो निर्णयों का हवाला दिया होगा, अर्थात्, लोननकुट्टी बनाम थॉम्मन (1976) 3 एससीसी 528 और नारायण प्रभु वेंकटेश्वर प्रभु बनाम नारायण प्रभु कृष्ण प्रभु (1977) 2 एससीसी 181, जो इस विषय पर काफी प्रकाश डालते हैं। अफसोस की बात है कि पक्षकारो के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इन दो पूर्व न्यायो पर हमारे सामने निष्कर्ष निकालने की उपेक्षा की है।

7. लोननकुट्टी निकटवर्ती भूमि के दो मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था। अपीलकर्ता की भूमि दो तरफ से नदी से घिरी हुई थी, जबकि प्रतिवादियों की भूमि, भूमि से घिरी हुई थी, जिसके कारण उत्तरदाताओं को अपनी भूमि की सीमा पर स्लुइस-गेट के साथ एक बांध का निर्माण करना पड़ा, ताकि वे अपीलकर्ता की भूमि से पानी ले सकें। मछली पकड़ने और कृषि के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करना और उसके

बाद पानी को उसी भूमि से वापस नदी की ओर मोड़ना। अपीलकर्ता, जो अपनी भूमि पर झींगा-मछली पकड़ने की खेती कर रहा था, बांध के निर्माण से व्यथित था और मानता था कि इससे उसकी झींगा मछली पकड़ने में बाधा उत्पन्न हुई है; इसलिए, उन्होंने उत्तरदाताओं के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। बदले में उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ निषेधाज्ञा का मुकदमा दायर किया और सुखभोग के अधिकारों का दावा किया। मुंसिफ न्यायालय द्वारा दोनों मुकदमों का अलग-अलग निपटारा किया गया और दोनों मुकदमों में इस आशय के आदेश पारित किए गए कि उत्तरदाताओं को केवल 'कृषि के संबंध में, लेकिन मछली पकड़ने के संबंध में सुखभोग का अधिकार नहीं है। डिक्री से, दोनों पक्षों द्वारा अपील के दो सेट पसंद किए गए, जिससे कुल मिलाकर चार अपीलें हुईं। जिला न्यायालय ने सभी अपीलें खारिज कर दीं और इस तरह डिक्री की पुष्टि की। इसके बाद उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता के मुकदमे से उत्पन्न निर्णयों के खिलाफ दूसरी अपील दायर की, लेकिन उनके अपने वाद से उत्पन्न अपीलों में कोई दूसरी अपील नहीं की गई। दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने तुरंत पूर्व न्याय की प्रारंभिक आपत्ति को यह कहते हुए दबा दिया कि प्रतिवादी के मुकदमे से उत्पन्न अपीलों में जिला अदालत द्वारा पारित आदेश अंतिम हो गए थे। हालाँकि, उच्च न्यायालय उस तर्क से प्रभावित नहीं हुआ, मुख्य रूप से नरहरि के मामले को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, और जिला न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द करने के बाद मामले को जिला न्यायालय में भेज दिया। जिला न्यायालय में रिमांड में उसके द्वारा अपनाए गए पिछले दृष्टिकोण की पुष्टि की गई, जिसके खिलाफ प्रतिवादी ने फिर से उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की, जिसे अनुमति दे दी गई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा एसएलपी दायर की गई। इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया एकमात्र और केंद्रीय मुद्दा यह था कि क्या मछली पकड़ने के प्रयोजनों के लिए अपीलकर्ता की भूमि के माध्यम से पानी

के प्रवाह को मोड़ने का प्रतिवादियों का अधिकार न्यायिक निर्णय द्वारा वर्जित है, और इस न्यायालय ने सकारात्मक उत्तर दिया। इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादियों ने, अपने स्वयं के मुकदमे से उत्पन्न अपीलों में जिला न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ आगे अपील दायर नहीं करके उस निर्णय को अंतिम और निर्णायक बनने दिया। इसने आगे देखा:

"वह निर्णय, जिसके खिलाफ अपील नहीं की गई है, अपीलकर्ता के मुकदमे से उत्पन्न दूसरी अपील में दोबारा नहीं खोला जा सकता है। मुद्दा यह है कि क्या उत्तरदाताओं को मछली पकड़ने के प्रयोजनों के लिए अपीलकर्ता की भूमि के माध्यम से पानी के प्रवाह का सहज अधिकार था या नहीं, यह सीधे और काफी हद तक था प्रतिवादी के मुकदमे में मुद्दे में। उस मुद्दे की सुनवाई की गई और अंततः जिला न्यायालय द्वारा उन्हीं पक्षों के बीच की कार्यवाही में निर्णय लिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील पर निर्णय लेने से पहले निर्णय दिया गया... जिला न्यायालय ने जिन परिस्थितियो में एक सामान्य निर्णय द्वारा 4 अपीलों को निस्तारित किया, धारा 11 के आवेदन को प्रभावित नहीं कर सकता... जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देने में उत्तरदाताओं की विफलता, जहां तक यह उनके मुकदमों से संबंधित है, धारा 11 के आवेदन को आकर्षित करती है क्योंकि किस हद तक जिला न्यायालय ने उत्तरदाताओं के खिलाफ उनके मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दों का फैसला किया, वह निर्णय न्यायिक के रूप में कार्य करेगा क्योंकि इसके खिलाफ अपील नहीं की गई थी।"

8. प्रभु में, पक्षकार एक ही नारायण प्रभु के वंशज थे। प्रतिवादी, नारायण प्रभु के चार बेटों में से तीसरे बेटे, ने सभी संबंधित वस्तुओं को संयुक्त परिवार की संपत्ति होने का दावा करते हुए सभी बेटों के खिलाफ विभाजन का मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ता, सबसे बड़े बेटे, ने प्रतिवादी के खिलाफ केवल इस आधार पर धन का

मुकदमा दायर किया कि उस मुकदमे में पार्टियों द्वारा संचालित तंबाकू की दुकानों का व्यापार उसकी स्व-अर्जित संपत्ति थी; परिणामस्वरूप, वह प्रतिवादी की दुकान पर पहुंचाए गए तंबाकू के कारण देय धन का हकदार था। विचारण न्यायालय ने दोनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई की और एक ही तारीख को दो डिक्री के माध्यम से उनका निर्धारण किया, यह मानते हुए कि विचाराधीन दुकानें संबंधित व्यक्तियों की थीं। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दोनों डिक्री के खिलाफ अपील की, और दोनों अपीलों पर अलग-अलग शीर्षकों के तहत निरंतरता में निर्णय लिया गया। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए दुकानों को तंबाकू के संयुक्त पारिवारिक व्यापार का हिस्सा माना और इस तरह मनी सूट को खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने विभाजन के मुकदमे में दिए गए फैसले और डिक्री पर आपत्ति जताते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जबकि धन के मुकदमे में फैसले और डिक्री को चुनौती नहीं दी गई। अपेक्षित रूप से, प्रतिवादी द्वारा पुनर्न्याय का मुद्दा उठाया गया था, जिसे अपीलकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देकर शांत करने की मांग की गई थी कि भारत के संविधान के असंशोधित अनुच्छेद 133(1)(सी) के तहत फिटनेस का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। मनी वाद के संबंध में और यह भी कि दोनों मुकदमों में पक्ष समान नहीं थे। इस न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों से असहमति जताते हुए कहा कि दो अलग-अलग डिक्री थीं। और अपीलकर्ता हमेशा अपील की विशेष अनुमति के लिए एक आवेदन के माध्यम से मनी वाद में उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता या अंतिमता को चुनौती दे सकता था और लोननकुट्टी में इस न्यायालय द्वारा लिए गए विचारों को मंजूरी दे सकता था और दोहराया:

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण I के अनुसार, "अभिव्यक्ति "पूर्व वाद", यह स्पष्ट करता है कि, यदि कार्यवाही शुरू होने से पहले कोई निर्णय दिया जाता है, जिसे पूर्व न्याय द्वारा वर्जित करने की मांग की जाती है, और उस निर्णय को

अंतिम बनने की अनुमति दी जाती है या कानून के संचालन से अंतिम बन जाता है, तो पूर्वन्याय की एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी।"

9. ओ एस 6/78 ट्रस्ट द्वारा किरायेदारों से बकाया किराए के रूप में 11468/- रुपये की राशि का दावा करते हुए दायर किया गया एक मुकदमा था। गौरतलब है कि तीन स्थानांतरित व्यक्तियों (जो ओ.एस.5/78 में प्रतिवादी 7 से 9 थे) को ट्रस्ट द्वारा स्पष्ट रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया था और इसके अतिरिक्त क्योंकि उनकी उपस्थिति उन मुद्दों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं थी जो ओ एस 6/78 और ओ एस 7/78 में उत्पन्न हुये। दावे ट्रस्ट से स्थानांतरितियों को हस्तांतरित भूमि के कथित हस्तांतरण से पहले की अवधि से संबंधित थे। यह भी उल्लेखनीय है कि किरायेदारों ने भी इस तथ्य के बावजूद अपने पक्ष की मांग नहीं की कि उन्होंने पहले ही ओएस 5/78 में अपने वादपत्र में उक्त हस्तांतरितियों के स्वामित्व की घेराबंदी कर दी थी और ओएस 6/78 और ओ.एस. 7/78 में अपने लिखित बयानों में विशेष रूप से ऐसा अनुरोध किया था। इस मुकदमे में, यह तर्क दिया गया था कि ट्रस्ट ने मुकदमे की जमीन उपरोक्त सर्वश्री पी. लक्ष्मणन, पी. वडिवेलु और पी. साईभाभा (ओ.एस.5/78 में प्रतिवादी 7 से 9 स्थानांतरित व्यक्ति हैं) को बेच दी थी। अन्य बातों के साथ-साथ, दलील दी गई कि 7000/- रुपये का अग्रिम किराया केवल किरायेदार द्वारा ट्रस्ट को सूट की संपत्ति सौंपने के समय ही चुकाने योग्य/समायोज्य था। चूँकि ओ एस 6/78 या ओएस 7/78 में दावा की गई राहत का स्थानांतरितियों के साथ कोई कारणता या संबंध नहीं था, इसलिए हमारी राय में उन्हें पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था। किरायेदारों का बचाव यह था कि ट्रस्ट एक सार्वजनिक मंदिर था जिसे श्री सेथुरामा चेट्टियार द्वारा बेचा/स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था और दूसरी बात यह कि किराए की बकाया राशि के रूप में दावा की गई राशि देय नहीं थी। कई अन्य दलीलें उठाई गई थीं, जिन पर हमें जोर देने की

आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालाँकि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि किरायेदारों ने इस बात से भी इनकार किया था कि कोई अतिरिक्त भूमि किराए पर ली गई थी। ओ.एस. 6/78 और ओ एस 7/78 में जिन छह मुद्दों पर चर्चा हुई, निम्नलिखित प्रासंगिक हैं और इसलिए, पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"(2) क्या प्रतिवादियों के कब्जे में संपूर्ण वाद संपत्ति ('ए' और 'बी' अनुसूची) दिनांक 8-11-67 के पट्टा विलेख के अंतर्गत आती है या क्या 'बी' के संबंध में कोई बाद में मौखिक समझौता हुआ था अकेले संपत्ति का शेड्यूल करें और यदि हां, तो इसकी लीज राशि क्या है?

(3) क्या वाद संपत्ति अधिनियम द्वारा शासित किसी सार्वजनिक मंदिर की है। यदि हां, तो क्या हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम की धारा 26 के तहत मंजूरी के अभाव में मुकदमा चलने योग्य है।

10. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, ओएस 6/78 को केवल 268/- रुपये की राशि के लिए डिक्री किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, अभिनिर्धारित करते हुये कि किरायेदार 11,468/- रुपये के किराए के दावे के मुकाबले 7000/- रुपये की अग्रिम राशि को मालिक की मंजूरी के बिना समायोजित नहीं कर सकते हैं; चूंकि मुकदमे की संपत्ति का स्वामित्व किसी सार्वजनिक मंदिर के पास नहीं था, बल्कि एक निजी ट्रस्ट के पास था, श्री सेथुरामा चेट्टियार की निजी संपत्ति होने के कारण, हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम की धारा 26 के तहत मंजूरी आवश्यक नहीं थी; और यह कि हस्तांतरित व्यक्ति स्थानांतरण/बिक्री द्वारा वाद संपत्ति के पूर्ण मालिक बन गए थे। सबसे महत्वपूर्ण रूप से, यह भी माना गया कि किरायेदारों को "वर्तमान मकान मालिक के स्वामित्व को चुनौती देने से रोका जाता है और वे किरायेदारी को छीनने के लिए

बाध्य हैं। उन्हें मकान मालिक या उसके उत्तराधिकारियों के शीर्षक पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है।" यह भी स्पष्ट रूप से बोधगम्य है कि सामान्य निर्णय ने तीनों मुकदमों में किरायेदारों के रुख के कारण मुकदमे की संपत्ति के शीर्षक और हस्तांतरणीयता के क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे ओ एस 5/78 के साथ-साथ ओ.एस.7/78 में डिक्री के खिलाफ अपील दायर करना अनिवार्य हो गया। .

11. ओएस 7/78 में, जैसा कि पहले ही बताया गया है, ट्रस्ट ने अनुसूची ए संपत्ति के पश्चिमी किनारे पर स्थित अनुसूची 'बी' में उल्लिखित भूमि के लिए कथित मौखिक पट्टे के संबंध में किराए के बकाया के रूप में 2600/- रुपये की वसूली की मांग की। किरायेदारों का बचाव यह था कि पूरी संपत्ति जिसमें अनुसूची 'ए' और 'बी' दोनों शामिल थीं, एक समग्र संपूर्ण थी, और दिनांक 8.11.67 के पटटाविलेख के माध्यम से 15 वर्ष की अवधि के लिये किराये पर दिया गया था। यह भी दलील दी गई कि मुकदमा एक सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा दायर किया गया था और इस प्रकार, जैसा कि तैयार किया गया था, सक्षम नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने माना कि संपूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति एक थी, जो उपरोक्त पंजीकृत लीज डीड द्वारा कवर की गई थी, और, तदनुसार, ओ.एस. 7/78 को लागत के साथ खारिज कर दिया गया। दिनांक 6.11.1982 के सामान्य निर्णय में यह सही ढंग से देखा गया है, जिसके द्वारा तीनों मुकदमों का निर्णय लिया गया है, कि ओएस 6/78 और ओएस 7/78 में तय किए गए मुद्दे 'एक और एक ही' थे। संक्षेप में, ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रस्ट हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1972 द्वारा शासित एक सार्वजनिक ट्रस्ट नहीं था और निजी ट्रस्ट द्वारा श्री सेथुरामा चेट्टियार के माध्यम से सर्वश्री पी लक्ष्मणन, पी. वाडिवेलु और पी. साईभाभा, को स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री की गई थी, कानून के विपरीत नहीं थे।

12. जैसा कि पहले ही प्रतिबिंबित और टिप्पणी की जा चुकी है, किरायेदारों ने केवल ओएस 6/78 के संबंध में अपील दायर की थी, हालांकि कुछ अप्रासंगिक मतभेदों

को छोड़कर, तीनों मुकदमों में सामान्य निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। यह सामान्य बात है कि मुद्दों को तय करने का दायित्व और कर्तव्य पूरी तरह से न्यायालय पर डाला गया है, जो फिर भी, उसके समक्ष मुकदमा करने वाले विरोधियों से सुझाव प्राप्त कर सकता है। आदेश XIV सीपीसी के तहत न्यायालय द्वारा निपटाए गए मुद्दे वाद के पक्षों के बीच संघर्ष के क्रिस्टलीकरण या विवाद के आसवन का गठन करते हैं, और तथ्य और/या कानून के विवादित प्रश्नों की प्रकृति में हैं। इस प्राथमिक कार्य का निर्वहन करते समय, न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह पक्षों की दलीलों का सार निकाले, उनके आरोपों और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सामग्री का विश्लेषण करे, और उसके बाद, मुद्दों को तैयार करने के लिए आगे बढ़े। हमारी राय में, जहां तक ओ.एस.5/78 का सवाल है, संपत्ति के स्वामित्व का प्रश्न आम तौर पर दो कारणों से उस मुकदमे के लिए अप्रासंगिक रहेगा। सबसे पहले, साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 पट्टेदार/लाइसेंसी को निर्माण करने से रोकती है यदि वह पट्टेदार/लाइसेंसधारक के स्वामित्व के संबंध में कोई चुनौती नहीं बना रहा है, यदि यह बाद वाला है तो उसने पूर्व को स्वामित्वाधीन/लाईसेंस प्राप्त परिसर पर कब्जा कर लिया है। मौजूदा मामले में, पहला पट्टा श्री सेथुरामा चेट्टियार द्वारा निष्पादित किया गया था और नवीनीकरण या अगला पट्टा एक ओर ट्रस्ट के माध्यम से इसके अध्यक्ष, श्री सेथुरामा चेट्टियार और दूसरी ओर किरायेदारों के बीच था। इसलिए, किरायेदारों को ट्रस्ट के स्वामित्व को चुनौती देने से कानूनी रूप से रोका गया, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला है, भले ही इस संदर्भ में ओ एस .5/78 में एक विशिष्ट मुद्दा नहीं उठाया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पक्षकारो को प्रतिद्वंद्वी मामलों के बारे में पता है, वहां किसी मुद्दे को औपचारिक रूप से तैयार करने में विफलता महत्वहीन हो जाती है, खासकर जब यह जुड़े मामलों में प्रमुखता से मौजूद हो और इस पर बिना किसी आपत्ति के व्यापक सबूत दर्ज किए गए हों। दूसरे, वादी के उचित अवलोकन पर,

यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होना चाहिए था कि ओएस 5/78 में वादी/किरायेदार को स्वामित्व वाले परिसर से बेदखली का डर था क्योंकि वे इसे अवैध हस्तांतरण मानते थे; लेकिन चूंकि सभी प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में कहा था कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मुकदमे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि जहां तक निषेधाज्ञा की प्रार्थना का सवाल है, बिना किसी देरी के फैसला सुनाया जाना चाहिए था। लेकिन, ट्रायल कोर्ट में किरायेदार की दलीलों के कारण पट्टे पर दी गई भूमि का स्वामित्व लड़ाई का आधार बन गया था, जिसमें उसने ट्रस्ट के साथ-साथ हस्तांतरितियों के स्वामित्व को बार-बार और दृढ़ता से चुनौती दी थी। किरायेदार को अपनी इच्छा या सुविधा के अनुसार, जिस विवाद पर उसने निर्णय लेने की मांग की है, उसे अस्वीकार करके या छोड़ कर अनुमोदन और पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

13. साक्ष्य अधिनियम का अध्याय आठ 'विबंध शीर्षक के अंतर्गत वर्तमान उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रावरणी में धारा 115 से 117 तक केवल तीन प्रावधान शामिल हैं। संदर्भ में आसानी के लिए हम धारा 116 को पुन: प्रस्तुत करेंगे-

"116. किरायेदार का विबंध; और कब्जे वाले व्यक्ति के लाइसेंसधारी का - अचल संपत्ति का कोई भी किरायेदार, या ऐसे किरायेदार के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति, किरायेदारी की निरंतरता के दौरान, इस बात से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि ऐसे किरायेदार के मकान मालिक के पास, किरायेदारी की शुरुआत में, ऐसी अचल संपत्ति का स्वामित्व था; और जिस व्यक्ति को उसके कब्जे वाले व्यक्ति के लाइसेंस से कोई अचल संपत्ति मिली हो, उसे इस बात से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि उस व्यक्ति के पास उस समय ऐसे कब्जे का अधिकार था जब ऐसा लाइसेंस दिया गया था।"

स्पष्ट रूप से, यह प्रावधान ट्रस्ट के स्वामित्व के लिए किसी भी चुनौती पर विचार करने से रोकता है क्योंकि बकाया किराए का दावा ट्रस्ट द्वारा हस्तांतरितियों, अर्थात् ओएस 5/78 में प्रतिवादी 7 से 9 को वाद भूमि की बिक्री से पहले की अवधि तक ही सीमित था। स्थिति काफी अलग होती, यदि उक्त प्रतिवादी 7 से 9 किरायेदारों के खिलाफ किराए के बकाया के लिए या उस मामले में, किसी अन्य राहत के लिए कोई दावा करते। इसका कारण यह है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 एक ओर किरायेदारों और दूसरी ओर स्थानांतरितियों के बीच किसी भी विवाद में लागू नहीं होगी।

14. हम सोचते हैं कि ओएस 5/78, ओएस 6/78 और ओ एस 7/78 के लिए सामान्य दिनांक 6.11.1982 के फैसले से निष्कर्ष निकालना विवेकपूर्ण है, क्योंकि यह कानूनी नोड का स्रोत, आधार है जिसे हमें सुलझाना है ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार राय दी है-

जब कोई ट्रस्टी सदस्य या सरकार मुकदमे की संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर रही है, तो यह ज्ञात नहीं है कि किरायेदार को यह संदेह क्यों होना चाहिए कि क्या वास्तविक शीर्षक मुकदमे की संपत्ति के वर्तमान खरीददारों को दे दिया गया है।

इसलिए वाद संपत्ति अधिनियम द्वारा शासित एक सार्वजनिक मंदिर नहीं है और चूंकि संपत्ति सेठरामा चेट्टियार की निजी संपत्ति पाई गई है, इसलिए हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम की मंजूरी ओ/एस.26 आवश्यक नहीं है। मुकदमे की संपत्ति सेथुरामा चेट्टियार की निजी संपत्ति है और इसे प्रतिवादी 7 से 9 को बेच दिया गया है, बाद वाले मुकदमे की संपत्ति के पूर्ण मालिक बन गए हैं और ओएस 5/78 में वादी को वर्तमान मकान मालिक के स्वामित्व को चुनौती देने से रोक दिया गया है और वे हैं

किरायेदारी का दायित्व संभालने के लिए बाध्य। उन्हें मकान मालिक या उसके उत्तराधिकारियों के स्वामित्व पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

परिणाम में, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त सबूत साबित करेंगे कि मुकदमा संपत्ति सेथुरामा चेट्टियार की निजी संपत्ति है और प्रदर्श ए.19 में दिनांक 30.6.76 की बिक्री विलेख वैध है और प्रतिवादी 7 से 9 अब असली मालिक हैं, संपत्ति के जो पट्टे की समाप्ति के बाद संपत्ति पर कब्जा करने के हकदार हैं। परिणामस्वरूप, मुद्दों का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

....

परिणामस्वरूप, ओ एस 5/78 को लागत सहित खारिज किया जाता है। ओएस 6/78 ऊपर की गणना के अनुसार लागत के साथ आंशिक रूप से तय किया गया है। ओएस 7/78 के संबंध में, चूंकि अदालत ने माना है कि पूरी संपत्ति एक है, इसलिए पीछे के हिस्से के लिए कोई पट्टा राशि नहीं हो सकती है और इसे लागत के साथ खारिज कर दिया गया है।

15. किरायेदारों ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील संख्या 581 /1983 दायर की, जिस पर 25 अप्रैल, 1997 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया गया। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि अंतरितियो को पहले मामले में किरायेदारों द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया था। अपील, हालांकि पूर्व किरायेदारों के अपने मुकदमे में ट्रायल कोर्ट के समक्ष ओ.एस. 5/78 में पक्षकार थ और चूंकि स्वामित्व के हस्तांतरण की कानूनी औचित्य के संबंध में किरायेदारों के पक्ष में कोई भी निर्णय हस्तांतरितियों के अधिकारों को नष्ट नहीं करेगा, तो गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, और चूंकि ओएस 5/78 को 'खारिज' कर दिया गया था, फिर भी, इसकी परवाह किए बिना, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई थी। श्री सेथुरामा चेट्टियार का प्रतिनिधित्व उनके कानूनी

प्रतिनिधियों के माध्यम से अपील 581/1983 में किया गया था, जिसे विशेष रूप से ओएस 6/78 के संबंध में प्राथमिकता दी गई थी। हमने किरायेदारों की अपील की सामग्री का अध्ययन किया है, और जैसा कि हमें उम्मीद थी, चुनौती का गंभीर कारण ट्रस्ट का सार्वजनिक चरित्र और प्रकृति और इसके हस्तांतरण की कानूनी अपूर्णता थी। यह इस विश्लेषण को भी पुष्ट करता है कि किरायेदारों द्वारा अपने मुकदमे में उठाए गए विवाद के साथ-साथ ट्रस्ट के मुकदमे में उनके बचाव का उल्लेख पिछले वाक्य में किया गया था। ये वाकई उल्लेखनीय है क्योंकि किरायेदार ओएस 5/78 में निर्णय की हानिकारक प्रकृति से पूरी तरह से अवगत था और इसने उसके अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से पंगु बना दिया है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि किरायेदार ने सीआरए संख्या 1/1993 के साथ एक समीक्षा दायर की थी, जिसे 19.3.1999 के एक विस्तृत निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। जहां तक पक्षकारो की दलीलों का सवाल है, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट किया था कि किरायेदारों ने किराए के बकाया के प्रति किसी भी दायित्व से इनकार किया था; किरायेदार ने तर्क दिया था कि ट्रस्ट के मुकदमे हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1972 की धारा 25 के तहत आवश्यक मंजूरी के अभाव में कानून में चलने योग्य नहीं थे; कि किरायेदार ने बिक्री विलेख दिनांक 1.7.1976 की वैधता को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि, हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1972 की धारा 25 को ध्यान में रखते हुए, यह अमान्य था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक विस्तृत और विवरणात्मक मंदिर/ट्रस्ट की संपत्ति की प्रकृति पर चर्चा कि यह पता लगाने के लिए कि क्या यह निजी या सार्वजनिक ट्रस्ट का हिस्सा है, हमने पहले ही इस बात पर प्रकाश डाला है कि किरायेदारों द्वारा दायर ओएस 5/78 को "खारिज" कर दिया गया था, फिर भी, इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की गई है। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें दर्ज

करने के बाद, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचार के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया: -

(i) क्या वादी द्वारा वाद संख्या 2, 3 और 4 पर विचारण कोर्ट के निष्कर्षों को विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा प्रचारित करने वाली वर्तमान अपील, उत्तरदाताओं के तर्क के अनुसार पुनर्न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है?

(ii) क्या उपरोक्त मुद्दों पर विद्वान ट्रायल जज द्वारा दिए गए निष्कर्ष सही हैं, कानून में वैध हैं और इस तरह टिकाऊ हैं?

(iii) क्या वादी दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी 7 से 9 के पक्ष में विक्रय-पत्र की वैधता पर सवाल उठाने का हकदार है?

(iv) पक्षकार किस राहत, यदि कोई हो, की हकदार हैं?

जाहिर है, ओ.एस. 5/78 अन्य की तरह ही केंद्र में थी, अन्यथा उपरोक्त (iii) उत्पन्न नहीं होता। यह स्पष्ट है कि सभी संबंधितों ने ग़लती से यह मान लिया कि अपील में ओएस .5/78 भी शामिल किया गया था।

16. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पलटवार करते हुए माना कि ओएस 6/78 में वादी एक सार्वजनिक ट्रस्ट था और तदनुसार, हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1972 के दायरे और परिधि में आता है। जहां तक किरायेदारों की विफलता का सवाल है ओएस . 5/78 की खारिज के खिलाफ अपील करने के लिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने, हमारी राय में, संदेहास्पद रूप से माना कि यह आवश्यक नहीं था क्योंकि किरायेदारों के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं था। जबकि हम इस बात की सराहना कर सकते हैं कि ओएस 5/78 में दायर अपने लिखित बयानों में प्रतिवादियों के रुख के कारण, वास्तव में, वादी के लिए कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन फिर भी, किरायेदारों का मुकदमा 'खारिज कर दिया गया था और इसलिए, कम से कम, अपील दायर करना और कम से

कम अत्यधिक सावधानी बरतते हुए उस पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना उचित और विवेकपूर्ण होता। वाद ओएस 5/78 की 'खारिज' इस राय का संकेत नहीं हो सकती है कि तथ्य और कानून के सभी दावे विचारण न्यायालय की राय में कानूनी रूप से अस्थिर थे, जिसमें यह भी शामिल है कि न्यास वाद की संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता था जिस तरह से यह हुआ. इसी कारण से किरायेदार को भी ओएस 6/78 के समान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के संबंध में ओएस 7/78 में फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए थी; चूंकि न्यास ने अपनी याचिका की अस्वीकृति पर हमला नहीं किया था कि एक अलग किरायेदारी ओएस 7/78 में दावे को नियंत्रित करती है, इसलिए फैसले का हिस्सा अंतिम हो गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस घटना में गलती से यह राय दी है कि पुनर्न्याय का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस स्थिति को खो दिया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 ने ट्रस्ट/मकान मालिक के स्वामित्व को किसी भी चुनौती को अस्वीकार्य और अक्षम बना दिया है, जिसने अपीलकर्ता को हस्तांतरित संपत्ति के कब्जे में डाल दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि किरायेदार ने हस्तांतरितियों को संपत्ति हस्तांतरित करने की ट्रस्ट/मकान मालिक की कानूनी क्षमता पर आपत्ति जताई थी। एर्गो, यह किसी का मामला नहीं था कि हालाँकि शुरुआत में ट्रस्ट के पास मुकदमे की संपत्ति का स्वामित्व था लेकिन बाद में उसने इसे खो दिया था। वास्तव में प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले में इस पहलू पर चर्चा करने की एक बड़ी चूक है, जिसने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि ट्रस्ट/मकान मालिक एक सार्वजनिक ट्रस्ट था और तदनुसार, ट्रस्ट की संपत्ति बेचने में अक्षम था। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने अंतरितियो को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना विचारण कोर्ट की राय को उलट दिया, जिन्हें किरायेदारों ने अपनी अपील में पक्षकार नहीं बनाया था, हालांकि वे किरायेदारों के मुकदमे में प्रतिवादी थे; वे उच्च

न्यायालय के समक्ष नहीं थे क्योंकि किरायेदार ने ओएस 5/78 की खारिज के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला किया था जिसमें उसने ये प्रश्न भी उठाए थे। यदि यह तर्क दिया जाता है कि सभी तीन मुकदमे एक सामान्य निर्णय द्वारा कवर किए गए थे, तो किरायेदार को अपनी अपील में स्थानांतरित लोगों को शामिल करना चाहिए था।

17. ट्रस्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष दूसरी अपील दायर की, लेकिन बेवजह और स्पष्ट रूप से उस वाद पर इसकी चुनौती को पूर्व न्याय का सिद्धांत के प्रभाव और प्रभाव के संबंध में केवल प्रथम अपीलीय न्यायालय की राय तक सीमित कर दिया। ट्रस्ट ने उस समय तक पहले ही संपत्ति बेच दी थी और उल्लेखनीय रूप से उनका एकमात्र निर्वाह हित 268/ रुपये की मामूली डिक्री राशि की वसूली के लिए था। हमें उम्मीद थी कि ट्रस्ट दृढ़तापूर्वक इस बात पर जोर देगा कि उसके हस्तांतरितियों के प्रतिकूल निर्णय उनकी अनुपस्थिति में कानूनी तौर पर नहीं दिया जा सकता था; और साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 ने किरायेदारों को ट्रस्ट के शीर्षक या कानूनी चरित्र को चुनौती देने से अक्षम कर दिया है, क्योंकि यह ट्रस्ट ही है जिसने किरायेदार को कब्जे में रखा था। हालाँकि, जैसा कि हुआ है, दूसरा अपीलीय न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या से सहमत है कि न्यायिक निर्णय किरायेदारों के खिलाफ लागू नहीं होता है।

18. संदर्भ की सुविधा के लिए सीपीसी की धारा 11 नीचे दी गई है:

रेस ज्यूडिकाटा- कोई भी अदालत ऐसे किसी मुकदमे या मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगी जिसमें संबंधित मामला सीधे तौर पर और काफी हद तक उन्हीं पक्षों के बीच एक मजबूत मुकदमे में चल रहा हो, या उन पक्षों के बीच जिनके तहत वे या उनमें से कोई दावा करता है, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा कर रहा है, ऐसे बाद के मुकदमे की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय में या वह मुकदमा जिसमें ऐसा मुद्दा बाद

में उठाया गया है, और सुना गया है और अंततः निर्णय लिया गया है ऐसे न्यायालय द्वारा.

स्पष्टीकरण 1. अभिव्यक्ति "पूर्व मुकदमा" एक ऐसे मुकदमे को इंगित करेगा जिसका निर्णय संबंधित मुकदमे से पहले किया गया है, चाहे वह उससे पहले संस्थित किया गया हो या नहीं।"

स्पष्टीकरण II.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय की क्षमता ऐसे न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील के अधिकार के किसी भी प्रावधान के बावजूद निर्धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण III.- उपरोक्त उल्लिखित मामला पूर्व मुकदमे में एक पक्ष द्वारा आरोपित किया गया होगा और दूसरे द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इनकार किया गया होगा या स्वीकार किया गया होगा।

स्पष्टीकरण IV-कोई भी मामला जिसे ऐसे पूर्व मुकदमे में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, उसे ऐसे मुकदमे में सीधे और महत्वपूर्ण रूप से मुद्दा माना जाएगा।

स्पष्टीकरण V -वादे में दावा की गई कोई भी राहत, जो डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अस्वीकार कर दी गई मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण VI.- जहां व्यक्ति किसी सार्वजनिक अधिकार या निजी अधिकार के संबंध में अपने और दूसरों के लिए साझे में दावा करते हैं, तो ऐसे अधिकार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार मुकदमा कर रहे व्यक्तियो के अधीन दावा माना जायेगा।

स्पष्टीकरण VII.- इस धारा के प्रावधान डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही पर लागू होंगे और इस धारा में किसी भी मुकदमे, मुद्दे या पूर्व मुकदमे के संदर्भ को क्रमशः डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही के संदर्भ के रूप में माना जाएगा; ऐसी कार्यवाहियो मे उत्पन्न होने वाला प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन सवालके लिये पूर्व कार्यवाही।

स्पष्टीकरण VIII.- किसी मुद्दे को सीमित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा सुना गया और अंतिम रूप से निर्णय लिया गया, जो ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेने में सक्षम है, बाद के मुकदमे में पूर्व न्यायिक के रूप में काम करेगा, भले ही सीमित क्षेत्राधिकार वाला ऐसा न्यायालय ऐसे बाद के मुकदमे की सुनवाई के लिए सक्षम नहीं था या वह मुकदमा जिसमें बाद में ऐसा मुद्दा उठाया गया हो।

इस न्यायालय की तीन समन्वय पीठों, पहले लोननकुट्टी, दूसरे प्रभु और तीसरे प्रीमियर टायर्स द्वारा दिए गए निर्णय पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

19. हमें श्योदान सिंह बनाम दरियाओ कुँवर (1966) 3 एससीआर 300 में चार-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें इस न्यायालय ने धारा 11 के पांच घटक तत्वों को स्पष्ट रूप से गिनाया है, अर्थात्: -

(i) बाद के मुकदमे या मुद्दे में सीधे तौर पर और काफी हद तक विवादग्रस्त मामला वही होना चाहिए जो पिछले मुकदमे में सीधे तौर पर और काफी हद तक विवादग्रस्त था;

(ii) पहला मुकदमा उन्हीं पार्टियों के बीच या उन पार्टियों के बीच का मुकदमा रहा होगा जिनके तहत वे या उनमें से कोई दावा करता है;

(iii) पार्टियों ने पूर्व मुकदमे में एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा दायर किया होगा;

(iv) जिस अदालत ने पहले मुकदमे का फैसला किया वह अगले मुकदमे या उस मुकदमे की सुनवाई के लिए सक्षम अदालत होनी चाहिए जिसमें बाद में ऐसा मुद्दा उठाया गया हो; और

(v) बाद के मुकदमे में सीधे और महत्वपूर्ण रूप से संबंधित मामले की सुनवाई पहले मुकदमे में अदालत द्वारा की गई होगी और अंततः निर्णय लिया गया होगा। इसके अलावा स्पष्टीकरण 1 से पता चलता है कि यह वह तारीख नहीं है जिस दिन मुकदमा दायर किया गया है, बल्कि वह तारीख है जिस दिन मुकदमा दायर किया गया है, इसलिए भले ही कोई मुकदमा बाद में दायर किया गया हो, यदि इसका निर्णय पहले हो चुका है तो यह एक पुराना मुकदमा होगा।

श्योदान सिंह के मामले में जो पहेली हमारे सामने पैदा हुई है, उससे थोड़ी ही अलग थी। अपीलीय न्यायालय को उन्हीं पक्षों के बीच पांच अलग-अलग मुकदमों की पांच अपीलों का सामना करना पड़ा, जिनमें मुद्दे समान थे। दो अपीलें खारिज कर दी गईं, हालांकि, योग्यता के आधार पर नहीं। यह उन परिसरों में था, जिन पर इस न्यायालय द्वारा तर्क दिया गया और स्वीकार किया गया कि पुनर्न्याय के सिद्धांत उन दो मुकदमों में पारित डिक्री के संबंध में लागू हो गए, जिनके संबंध में दायर की गई अपीलें खारिज कर दी गई थीं। यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि अन्यथा "हारने वाली पार्टी को ट्रायल कोर्ट द्वारा गुण-दोष के आधार पर दिए गए निर्णय के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अपील दायर करनी होगी और उस अपील को कुछ प्रारंभिक आधार पर खारिज कर देना होगा, जिसके परिणामस्वरूप पार्टियों के बीच गुण-दोष के आधार पर दिया गया निर्णय भी बेकार हो जाता है।" श्योदान सिंह ने उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों पर ध्यान दिया, जिन्होंने मामले के गुण-दोष के हित में स्पष्ट रूप से प्रक्रियात्मक तकनीकीयो को नजरअंदाज करना पसंद किया, लेकिन अपनी अंतिम राय

नहीं बताई, जिसने हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया ताकि अलग-अलग विचारों में हस्तक्षेप किया जाए और असंगति को दूर किया जाए।

20. ऐसे मामलों में पुनर्निर्णय की प्रयोज्यता के मुद्दे पर जहां दो या दो से अधिक मुकदमों का निपटारा एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया है, लेकिन अलग-अलग डिक्री द्वारा, और जहां एक मुकदमे में डिक्री के खिलाफ अपील की गई है, लेकिन अन्य के खिलाफ नहीं, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी राय और निर्णय दिए गए। मद्रास उच्च न्यायालय और लाहौर, नागपुर और अवध के पूर्ववर्ती उच्च न्यायालयों ने माना है कि ऐसे मामलों में कोई न्यायिक निर्णय नहीं हो सकता है, जबकि इलाहाबाद, कलकत्ता, पटना, उड़ीसा के उच्च न्यायालयों और रंगून के पूर्व उच्च न्यायालयों ने इसके विपरीत विचार रखे हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक ही उच्च न्यायालय के भीतर भी परस्पर विरोधी निर्णयों के उदाहरण हैं। लछमी बनाम भुल्ली [एआईआर (1927) लाह 289] और पूर्ण पीठ में लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में टेक चंद, जे. का निर्णय और पंचंदा वेलन बनाम वैथीनाथ सस्त्रियल [आईएलआर (1906) 29 मद 333] में मद्रास उच्च न्यायालय का और बी. शंकर सहाय बनाम बी. भागवत सहाय [एआईआर 1946 अवध 33 (एफबी)] में अवध उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ का निर्णय पूर्व न्याय की प्रयोज्यता के विरुद्ध अग्रणी निर्णय प्रतीत होता है। उन मामलों के विवरण का उल्लेख किए बिना, यह नोट करना पर्याप्त है कि कठोर न्यायिक निर्णय की प्रयोज्यता के प्रति झिझक या अनिच्छा इस धारणा से उत्पन्न हुई कि संहिता की धारा 11 केवल "मुकदमों" को संदर्भित करती है और इसमें शामिल नहीं है इसके दायरे में "अपील"; चूंकि संबंधित मुकदमों में आए फैसले एक साथ व्यक्त किए गए थे, इसलिए उक्त धारा द्वारा निर्धारित कोई "पूर्व मुकदमा" नहीं हो सकता है; एक साथ विचार किए गए संबंधित मुकदमों में सार, मुद्दे और निष्कर्ष सामान्य या काफी हद तक समान होने के कारण, उनमें से एक या

अधिक मुकदमों के खिलाफ अपील दाखिल न करने से योग्यता के आधार पर अन्य अपीलों पर विचार करने से नहीं रोका जाना चाहिए; और यह कि पूर्व न्याय का सिद्धांत उस निर्णय पर लागू होगा, जो सामान्य है, न कि उस सामान्य निर्णय के आधार पर निकाले गए निर्णयों पर।

21. वहीं, ज़हरिया बनाम देबिया आईएलआर (1911) 33 ऑल 51 मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच का फैसला और इसुप अली बनाम गौर चंद्र देब 37 कैल एलजे 184: एआईआर 1923 कैल 496 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले और श्रीमती गेट्रूड ओस्टेस बनाम श्रीमती मिलिसेंट डी'सिल्वा आईएलआर 12 पट 139 ; एआईआर 1933 पट 78 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय इसके विपरीत धारणा के हैं। ये निर्णय बड़े पैमाने पर इस भविष्यवाणी पर आगे बढ़े कि वाक्यांशवाद "मुकदमा" प्रथम दृष्टया न्यायालय या ट्रायल कोर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपीलीय न्यायालयों के समक्ष इसके डोमेन की कार्यवाही में शामिल है; निर्णय की गैर-प्रयोज्यता असंगत डिक्री और विरोधाभासी डिक्री को जन्म दे सकती है, न केवल डिक्री की बहुलता के कारण, बल्कि पार्टियों की बहुलता के कारण भी, और इस प्रकार भ्रम पैदा होता है कि निष्पादन में किस डिक्री को प्रभावी किया जाना है; एक डिक्री तब तक वैध है जब तक कि वह अमान्य न हो और उसे किसी अन्य डिक्री के खिलाफ शुरू की गई अपीलीय कार्यवाही में खारिज या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है; कि न्यायिक निर्णय का मुद्दा आदेश के संदर्भ में तय किया जाना है, जो सीपीसी की धारा 96 के तहत अपील योग्य हैं और फैसले के संदर्भ में नहीं (जिसे अलग तरह से परिभाषित किया गया है), लेकिन सीपीसी में डिक्री के संबंध में; धारा 11 के स्पष्टीकरण II के मद्देनजर अपीलीय कार्यवाही में किसी डिक्री की पुष्टि न होने का कोई परिणाम नहीं होता है, जहां तक कि यह सीमा अवधि समाप्त होने पर अंतिम रूप से पहुंचता है, जो प्रदान करता है कि न्यायालय की क्षमता किसी भी स्थिति में निर्धारित की जाएगी। ऐसे

न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील के अधिकार के संबंध में कोई प्रावधान; और सीपीसी की धारा 11 पूर्व न्यायिक सिद्धांत के बारे में संपूर्ण नहीं है, जो कानून और सार्वजनिक नीति के सामान्य सिद्धांतों से उत्पन्न होती है।

22. प्रक्रियात्मक मानदंड, तकनीकीताएं और प्रक्रियात्मक कानून वर्षों के अनुभवजन्य अनुभव के बाद विकसित होते हैं, और उन्हें अनदेखा करना या उन्हें कम महत्व देना अनिवार्य रूप से न्याय को पराजित करता है। जहां उन मामलों में एक सामान्य निर्णय दिया गया है जिनमें समेकन आदेश विशेष रूप से पारित किए गए हैं, हमें लगता है कि यह अनूठा है कि एक ही अपील दायर करने से पूरा विवाद एक बार फिर से विचाराधीन हो जाता है। सीपीसी की धारा 151 द्वारा न्यायालयों को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करने के आधार पर समेकन आदेश पारित किए जाते हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने चितिवलसा जूट मिल्स बनाम जेपी रीवा सीमेंट (2004) 3 एससीसी 85 में स्पष्ट किया था। सामान्य मुद्दे तय कर दिए गए हैं और एक सामान्य सुनवाई आयोजित की गई है, हारने वाले पक्ष को आंशिक रूप से प्रतिकूल या विपरीत बोलने वाले निर्णयों पर भी स्थापित सभी प्रतिकूल डिक्री के संबंध में अपील दायर करनी होगी। ऐसा मत व्यक्त करते समय हमारा इरादा इस सिद्धांत को कमजोर करने का नहीं है कि किसी निर्णय में निहित प्रत्येक असुविधाजनक या अप्रिय या अनुचित या प्रतिकूल निष्कर्ष या अवलोकन के खिलाफ अपील दायर करने की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन यह क्रॉस-आपत्ति के माध्यम से किया जा सकता है यदि अवसर उत्पन्न होता है। उसके बाद जिस डिक्री पर हमला नहीं किया गया वह "पूर्व वाद " के चरित्र में रूपांतरित हो गया। यदि इसे इस तरह से नहीं देखा जाना है, तो केवल सूट बी में डिक्री को चुनौती देकर वाद में पारित डिक्री को शून्य करना संभव होगा। कानून किसी पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देना अभिशाप मानता है जब यह जानबूझकर या लापरवाही से इस उददेश्य के लिये सीधे कार्यवाही शुरू करने में विफल

रहा हो। प्रक्रिया के कानूनों को बड़ी ही खूबसूरती से न्याय के लिए सहायक कहा गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें लापरवाही से नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है, तो अनिवार्य रूप से और अपरिहार्य रूप से न्याय का गर्भपात हो जाएगा। वैधानिक कानून और प्रक्रियात्मक कानून न्यायिक ढांचे के दो पहलू हैं, प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत हैं। मौजूदा मामले में, क्या किरायेदार ने कम से कम ओ.एस. 5/78 के संबंध में डिक्री के खिलाफ अपील दायर की थी?, कानूनी पहेली जो स्वयं प्रकट हुई है और इतना न्यायिक समय समाप्त हो गया है, वह उत्पन्न ही नहीं हुई होगी।

23. आक्षेपित में उल्लेख करते हुये, सज्जादानशीन सईद बनाम मूसा दादाभाल उमर एआईआर 2000 एससी 1238 में इस न्यायालय के निर्णय पर, खंडपीठ ने मुकदमे के एक पहलू के बीच अंतर को रेखांकित किया जो कि संपार्श्विक और आकस्मिक है, जबकि उस पहलू के विपरीत जो सीधे और काफी हद तक सवाल पर केंद्रित है। जिसका निर्धारण ही निर्णय का तात्कालिक आधार है। होआग बनाम न्यू जर्सी (1958) 356 यू.एस. 464 में न्यायिक न्याय का गठन क्या होता है, इसके प्रतिपादन का भी संदर्भ लिया गया था, अर्थात् यह महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत आकर्षित होता है "यदि औपचारिक परीक्षण के रिकॉर्ड से पता चलता है कि निर्णय बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था विशेष मामले पर निर्णय लेने के बाद, यह माना जाएगा कि पार्टियों के बीच भविष्य की सभी कार्रवाइयों के लिए उस मामले का निपटारा हो गया है।" खंडपीठ ने ईशर सिंह बनाम सरवन सिंह, एआईआर 1965 एससी 948 में इस न्यायालय की टिप्पणियों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए दलीलों और मुद्दों की जांच की आवश्यकता थी कि क्या प्रश्न पर सीधे और पर्याप्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। खंडपीठ ने यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि ओएस 5/78 पर तैयार किया गया मुददा संख्या 2 पूरी तरह से अनावश्यक और दोषपूर्ण था, असरार

अहमद बनाम दरगाह कमेटी, अजमेर, एआईआर 1947 पीसी 1 और प्रागदासजी गुरु भगवानदासजी बनाम पटेल ईश्वरलालभाई नरसिभल, एआईआर 1952 एससी 143 पर भी विचार किया। खंडपीठ ने माना कि उस मुद्दे पर निष्कर्ष अनावश्यक थे, अंतिम निर्णय के लिए न्यूनतम आधार का गठन नहीं करते थे और इसलिए, पुनर्निर्णय का गठन नहीं किया जाएगा। हमारी राय में, हमने पहले ही ऊपर संकेत दिया है कि, यदि ओएस 5/78 केवल निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा था, क्योंकि उसमें प्रतिवादियों (ट्रस्टी और ट्रांसफरी दोनों) ने अपने संबंधित लिखित बयानों में कहा था कि उनका वादी/किरायेदार को बेदखल करने का कोई इरादा नहीं था, तो यह मुकदमा नहीं होना चाहिए खारिज कर दिया गया है लेकिन डिक्री किया जाना चाहिए था। हमने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि किरायेदार ने वादपत्र में एक विशिष्ट और स्पष्ट दावा किया था कि ट्रस्ट द्वारा हस्तांतरित भूमि का हस्तांतरण पुडुचेरी हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1972 की धारा 26 के अनुरूप नहीं था। हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि यह किरायेदार द्वारा ओएस 6/78 और ओएस 7/78 में अपने लिखित बयान में उठाई गई एक महत्वपूर्ण आपत्ति थी। यह हमारे लिए असंगत प्रतीत होता है कि नष्ट किए गए परिसर के स्वामित्व को ओएस 5/78 में अप्रासंगिक माना जाए, लेकिन फिर भी यह ओएस 6/78 और ओएस 7/78 में विवादों का मूल या सार या आधार है। न्यायालय द्वारा अपनाई गई द्वंद्वात्मकता दृढ़तापूर्वक स्थिर रहनी चाहिए - यदि शीर्षक सरलता से निषेधाज्ञा के दावे के रूप में अप्रासंगिक था, तो यह बकाया राशि के दावे के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 का लाभ प्राप्त करने वाली पार्टी के संबंध में भी ऐसा ही था, अपने किरायेदार से बकाया राशि की मांग के संबंध में। यह नज़रअंदाज करना तर्कसंगत नहीं होगा कि किरायेदार की ओर से सभी तीन मुकदमों में दलीलें आम थीं, और विवाद के इस पहलू पर सभी तीन मुकदमों में किरायेदारों द्वारा दावा किया गया था। तीनों मुकदमों में किरायेदार की दलीलों को

समग्र और व्यापक रूप से पढ़ने पर, यह अपरिहार्य है कि किरायेदार ने अपनी दलीलों में जानबूझकर, सीधे और अपनी दलीलों में स्पष्ट रूप से नष्ट किए गए परिसर के स्वामित्व और हस्तांतरितियों को भूमि हस्तांतरित करने के लिए ट्रस्टियों की कानूनी क्षमता का प्रश्न उठाया। यह सामान्य सूत्र है जो तीनों मुकदमों में किरायेदार की दलीलों से गुजरता है। यह सच है कि यदि ओएस 5/78 सरलता से निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा था, और ट्रस्टियों और ट्रांसफरियों के रुख के मद्देनजर कि किरायेदारों को उनके निष्कासन के संबंध में कोई खतरा नहीं बढ़ाया गया था, तो स्वामित्व के लिए कोई भी संदर्भ या चुनौती पूरी तरह से अप्रासंगिक थी। लेकिन स्वामित्व का मुद्दा विशेष रूप से किरायेदार द्वारा उठाया गया था, जिसने इस प्रकार तीनो मुकदमो मे इसे सीधे और पर्याप्त रूप से विवाद में डाल दिया था। जहां तक वाद संख्या 6/78 और 7/78 का सवाल है, वे भी किराए की वसूली के लिए सरल मुकदमे थे जिनमें स्वामित्व से संबंधित बचाव भी प्रासंगिक नहीं था; किरायेदार के पास ओएस 6/78 में अपील दायर करने का कोई ठोस कारण उत्पन्न नहीं हुआ था क्योंकि डिक्री का मौद्रिक हिस्सा अपेक्षाकृत महत्वहीन था। जाहिर है, किरायेदार का संकल्प मुकदमे में स्वामित्व को केंद्रीय विवाद बनाना था और इन परिस्थितियों में स्वामित्व के पहलू पर गोलमोल बात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तार्किक रूप से, यदि स्वामित्व का प्रश्न प्रासंगिक था और ओ.एस. 6/78 में विचार करने योग्य था, यह ओएस 5/78 में भी प्रासंगिक था। इस तरह से देखने पर, हमें लगता है कि यह एक अपरिहार्य निष्कर्ष है कि किरायेदार द्वारा ओएस 5/78 के संबंध में भी अपील दायर की जानी चाहिए थी। न्यायिक कार्यवाही की कठोरता के डर से और खारिज आदेश को सही करने के लिए भी। हमारी राय में, किरायेदार पूरी तरह से गैर-अनुकूलित था जब यह माना गया कि उसके पक्ष में कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ था और मुकदमा 'खारिज' कर दिया गया था। उस खोज को नज़रअंदाज करना और उसे अंतिम मान लेना उस निष्कर्ष

को बदलने के लिए अभेद्य बना देता है। शेओपरसेन सिंह बनाम रामनंदन प्रसाद सिंह, (1915-16) 43 I.A.91 में, प्रिवी काउंसिल ने कहा - "पूर्वन्याय सार्वभौमिक अनुप्रयोग का एक प्राचीन सिद्धांत है और न्यायशास्त्र की हर सभ्य प्रणाली में व्याप्त है। यह सिद्धांत सभी न्यायिक में मूल सिद्धांत को समाहित करता है, ऐसी प्रणालियाँ जो प्रदान करती हैं कि समान पक्षों के बीच समान विषय वस्तु पर पहले का निर्णय निर्णायक होता है।" कारण और सार्वजनिक नीति जिस पर पूर्व न्याय समर्पित है, वह यह है कि जिस पक्ष ने मुकदमेबाजी में कोई पहलू उठाया है और उस पर कोई मुद्दा उठाया है, उसके पास उस संबंध में प्रमुख सबूत हैं, और उस बिंदु पर तर्क दिया है, एक बार जब वे अंतिम रूप प्राप्त कर लेते हैं तो जिज्ञासात्मक निष्कर्षों द्वारा बाध्य रहता है। किसी भी पक्ष को एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए; यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए; चुनौती के अभाव में न्यायिक निर्णय को सही माना जाना चाहिए। कानून के जिस पहलू पर अब विचार किया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या एक मामले में एक सामान्य फैसले के खिलाफ अपील दायर करना सभी मामलों में अपील दायर करने के समान है।

24. पूर्वन्याय का प्रयोग अक्सर विवादों को जन्म देता है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस न्यायालय में भी दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अलग-अलग राय व्यक्त की गई थी, जिसके कारण अपील को बड़ी पीठ के पास भेजने की आवश्यकता हुई। यही कारण है कि हमने विवाद से विस्तार से निपटना उचित समझा। हमें ऐसा लगता है कि यदि लोननकुट्टी और प्रभु के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों को पहले ही हमारे विद्वान और सम्मानित भाइयों के ध्यान में लाया गया होता, जब इस अपील की सुनवाई दो न्यायाधीशों की पीठ ने की होती, तो राय में विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के नतीजे का भी यही हश्र हुआ होगा। उपरोक्त विश्लेषण पर, विशेष रूप से तीन समन्वय पीठों द्वारा कानून

के पिछले प्रतिपादन पर, हम अपने विद्वान भाई अशोक कुमार गांगुली की राय से सहमत हैं कि अपील की स्वीकार किया जाना चाहिए। हमारी राय है कि ओएस 5/78 और ओएस 7/78 में डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने में असफल या उपेक्षित या ठोस रूप से टालने के कारण उत्तरदाताओं/किरायेदारों का मामला स्थायी रूप से सील कर दिया गया था और उनके खिलाफ न्यायिक निर्णय लागू होने के बाद से जब्त कर लिया गया था। हम तदनुसार इस अपील को स्वीकार करते हैं लेकिन अलग-अलग फैसलों को ध्यान में रखते हुए लागत के संबंध में कोई भी आदेश देने से इनकार करते हैं।

विभूति भूषण बोस

अपील स्वीकार गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।